P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-12* (Part-1) March- 2019
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का महत्व (1952–2006)

वाई0एन0 त्रिपाठी
विभागाध्यक्ष,
इतिहास विभाग,
आगरा कॉलेज, आगरा,
उत्तर प्रदेश, भारत

सुनीता
शोधार्थी,
इतिहास विभाग,
आगरा कॉलेज, आगरा,
उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

स्वाधीनता के पूर्व ग्रामीण उत्थान के लिये अनेक प्रयास किये गये। महात्मा गांधी का वर्धा (1937), रवीन्द्र नाथ ठाकुर का शान्ति–निकेतन (1921), स्पेन्सर हैज का केरल (1928), एफ0 एल0 वायले (1927) का गुड़गांव तथा एस0के0 डे का नीलोखेड़ी (1947) में चलाये गये कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण स्थान है। महात्मा गांधी का विचार था कि प्रत्येक गांव को सबसे पहले पर्याप्त अनाज, कपड़ा तैयार करने के लिए पर्याप्त रूई पैदा करनी चाहिए। उन्होंने खादी के प्रयोग, ग्रामोद्योग द्वारा आर्थिक उन्नति, धान कूट कर चावल तैयार करना, गुड़ बनाना, तेल पेरना, कपड़ा बुनना, नीम का तेल बनाना, मृत पशुओं के चमड़े से जूते तैयार करना, हाथ से कागम बनाना, शहद की मक्खियों को पालना, ऊनी कम्बल तैयार करना, मूल और प्रौढ़ शिक्षा एवं प्राकृतिक चिकित्सा पर जोर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों से बेरोजगारी दूर करने, वहां से संस्कृति में आवश्यक परिवर्तन तथा लोगों को आत्मनिर्भर देखने के लिए वे बराबर चिन्तित तथा इच्छुक थे। वे चाहते थे कि गांव की प्रत्येक वस्तु गांव से ही निर्मित की जाए और भारत का प्रत्येक गांव अपनी आवश्यकताओं को उपलब्ध कराने के बारे में आत्मनिर्भर हो जाए।

रवीन्द्र नाथ ठाकुर का नाम ग्राम पुनर्निर्माण के लिये सर्वदा स्मरणीय रहेगा। उनके विचार से ग्रामीण पुनर्निर्माण की प्रमुख समस्या गरीबी और बेकारी तक ही सीमित नहीं थी बल्कि उनकी योजना का उद्देश्य ग्रामवासियों के जीवन में आनन्द और स्फूर्ति का संचार करना था। सन् 1914 में बोलपुर में श्रीनिकेतन की स्थापना की जिससे ग्रामवासियों को अपनी समस्याओं को सुलझाने में काफी सहायता मिली।

पूना की सर्वेन्ट्स ऑफ इण्डिया सोसाइटी ने ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिये मद्रास, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में कृषि तथा प्रशिक्षण के लिए स्कूलों की स्थापना की।

सन् 1921 में वाई. एम.सी.ए. के कुछ नेताओं ने त्रिवेन्द्रम से 25 मील दक्षिण सार्थनदम में ग्रामीण कल्याण की योजना प्रारम्भ की जिसका मुख्य उद्देश्य आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से ग्रामीण जीवन को उच्च करना था। स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1952 को देश के 55 विकास खण्डों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में ग्रामीण जीवन में सर्वांगींण विकास के लिए स्थानीय जन सहयोग से विभिन्न विकास कार्यक्रमों का ऐतिहासिक आरम्भ हुआ।

तदन्तर ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक परियोजनाएं चलाई जाती रहीं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मूल उद्देश्य ग्रामीणों को आर्थिक दृष्टि स्वावलम्बी बनाना तथा स्थानीय जन भागीदारी के माध्यम से सरकारी परियोजनाओं में प्रत्यक्ष सहयोग से सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति के नवीन आयाम स्थापित करना था।

मुख्य शब्द : सामुदायिक, ग्राम विकास, कृषि, उद्योग, जन भागीदारी, सृजन, गरीबी उन्मूलन, स्वरोजगार ।

प्रस्तावना

सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अनुसार, ''सामुदायिक परियोजना का उद्देश्य परियोजना क्षेत्र में स्थित पुरुषों, स्त्रियों एवं बच्चों के लिए संस्थापन में मार्गदर्शक के समान सेवा करना, जीवन के अधिकार का भोजन–मुख्य विषय जिसके साथ में योजना के प्रारम्भिक स्तरों में इस उद्देश्य के लिए प्राथमिक शक्ति प्राप्त करना।[1]

शोध कार्य का उद्देश्य

1. भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करना।
2. सामुदायिक विकास के उद्देश्य तथा व्यापकता का अध्ययन करना।
3. सामुदायिक विकास कार्यक्रम में सम्मिलित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का अध्ययन करना।
4. सामुदायिक विकास कार्यक्रम की सफलता तथा महत्व का अध्ययन करना।

साहित्यावलोकन

1. गुप्त विजय प्रकाश गुप्ता, मोहनी 2001 : भारत में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन दिल्ली। इस ग्रन्थ में लेखक ने भारत के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन पर विस्तृत लेखन किया है। स्वतंत्र भारत में पंचवर्षीय योजनाओं तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर भी प्रकाश डाला गया है।
2. जैन, बी.एस. भारत में कृषि विकास, दिल्ली 2000 : इस पुस्तक में लेखक ने 1950 से लेकर 2000 तक कृषि के विकास का वर्णन किया है।
3. सिंह, निर्मल, 1990 , लोक भारती, इलाहाबाद। पंचवर्षीय योजनाओं में उ0प्र0 में कृषि का विकास, उ0प्र0 का भौगोलिक एवं आर्थिक वर्णन : इस पुस्तक में उ0प्र0 में सामुदायिक विकास के विभिन्न कार्यक्रमों का वर्णन किया गया है तथा पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत धन का आवंटन इत्यादि पर प्रकाश डाला गया है।
4. सिंह, विद्यासागर, (2001) : कृषक श्रमिकों की आर्थिक स्थिति का तथ्यपरक अध्ययन, इस ग्रन्थ में विशेषतः वाराणसी जनपद के संदर्भ में विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रम तथा योजनाओं में कृषकों की आर्थिक स्थिति पर प्रभाव का अध्ययन किया गया है।
5. जौहर, एस0एस0 1964 : भारत में सामुदायिक विकास, नई दिल्ली। इस पुस्तक में भारत में सामुदायिक विकास की पृष्ठभूमि के रूप में इटावा में 1948 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विभिन्न विकाखण्डों में कृषि की उन्नति के लिए विभिन्न तकनीकों तथा ग्रामीण नवयुवकों को विकास के कार्यक्रमों में सम्मिलित करके उनका आर्थिक एवं सामाजिक विकास करना था।

विषय विस्तार

भारत सरकार के सामुदायिक मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम के आठ उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया है, जो इस प्रकार है–

1. ग्रामीण जनता के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करना।
2. गांवों में उत्तरदायी एवं क्रियाशील नेतृत्व का विकास करना।
3. सभी ग्रामवासियों को आत्मनिर्भर एवं परिवर्तनशील बनाना।
4. समस्त ग्रामीण जनता के आर्थिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए एक ओर कृषि का आधुनिकीकरण तथा दूसरी ओर ग्रामीण उद्योगों का विकास करना।
5. उपर्युक्त सभी सुधारों को व्यावहारिक रूप प्रदान करने के लिए ग्रामीण स्त्रियों और परिवारों की दशा को उन्नत करना।
6. राष्ट्र के भावी नागरिकों के व्यक्तित्व का समुचित विकास करना।
7. ग्रामीण शिक्षकों के हितों की रक्षा करना।
8. सभी ग्रामीणों के स्वास्थ्य का स्तर उन्नत करना और बीमारी से उनकी रक्षा करना।

'सामुदायिक विकास' आधुनिक युग का एक अत्यन्त लोक प्रचलित शब्द है। एक कार्यक्रम के रूप में इसका प्रसार विगत वर्षों में प्रारम्भ हुआ जिसे मुख्य रूप से अविकसित देशों में अपनाया गय। सामुदायिक विकास योजना की व्यवस्था के लिये अनेक प्रयत्न किये गये हैं। वास्तव में सामुदायिक विकास एक ऐसी योजना है जो आत्म सहायता व सहयोग के सिद्धान्तों के आधार पर स्वावलम्बी उपायों से सामाजिक और आर्थिक उन्नति पर बल देती है। विद्वानों ने सामुदायिक विकास की अनेक परिभाषाएं दी हैं।

''सामुदायिक योजना नियमित रूप से समुदाय के कार्यों का प्रबन्ध करने के लिये अच्छी तरह से सोची हुई योजना है।[1]

''सामुदायिक विकास योजना एक विधि है जो समुदाय के लिये उसके पूर्ण सहयोग से आर्थिक और सामाजिक विकास की परिस्थितियों को पैदा करती है और पूर्णरूप से समुदाय की पहल पर निर्भर करती है।''[2]

सामुदायिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सामुदायिक जनशक्तियों का प्रयोग उनके स्वयं के प्रयासों से एकत्रित करने, सम्बन्धित सरकारी एवं गैर–सरकारी कर्मचारियों द्वारा सामुदायिक आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति को उच्च करने तथा सामुदायिक जीवन को राष्ट्रीय जीवन में परिवर्तित करने जैसे कार्यों को सम्मिलित किया जाता है। मूलरूप से सामुदायिक विकास में दो बातें सम्मिलित हैं। प्रथम अपनी वर्तमान स्थिति को उठाने के लिए सदस्यों की विकास कार्यों में सहभागिता और द्वितीय विकास के लिए तकनीकी एवं अन्य आवश्यक साधनों की उपलब्धता।

इस कार्य में न केवल समुदाय की आर्थिक, तकनीकी एवं वैज्ञानिक स्थितियों में ही परिवर्तन लाया जाता है बल्कि सामुदायिक मूल्यों एवं व्यावहारिक पद्धतियों में भी। परम्परा में जकड़े होने के कारण ग्रामीण लोग धीरे–धीरे ही आधुनिक बातों में विश्वास करते हैं। अतः आवश्यक है कि सदस्यों के विचारों, मनोवृत्तियों एवं भावनाओं में धीरे–धीरे परिवर्तन लाया जाये जिससे वे अपनी परम्परागत रूढ़ियों में अनुकूल परिवर्तन ला सकें और उपलब्ध सरकारी एवं गैर सरकारी साधनों का उपयोग कर अपने व्यावहारिक जीवन को परिवर्तित कर सकें।

इस प्रकार सामुदायिक विकास कार्यक्रम समयानुरूप विभिन्न कार्यक्रमों के रूप में चलते रहे हैं। ग्रामीण विकास में इसका विशेष योगदान रहा है। अन्य विकास योजनाओं के समान सामुदायिक विकास कार्य के कुछ प्रमुख उद्देश्य हैं जिनकी पूर्ति के लिए समय–समय पर जरूरतमन्द समुदायों में विकासात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मूल रूपेण सामुदायिक विकास योजनाओं का मुख्य उद्देश्य सरकारी सहायता एवं जन सहयोग से ग्रामीण जीवन का सामजिक एवं आर्थिक विकास करना है। इसके अतिरिक्त सामुदायिक विकास के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं :–

1. कृषि उत्पादन एवं ग्रामीण उद्योगों में बढ़ोत्तरी कर पारिवारिक आमदनी को बढ़ावा देना।
2. जन सहयोग के माध्यम से लोक कल्याणकारी कार्यों जैसे सड़क निर्माण, विद्यालय भवन निर्माण आदि कार्यों को प्रोत्साहन देना।
3. स्वास्थ्य एवं सफाई को बनाये रखना तथा बढ़ावा देना।
4. शिक्षा, मनोरंजन एवं बाल प्रशिक्षण कार्यों को बढ़ावा देना।
5. ग्रामीण संस्कृति, रूढ़ियों, मूल्यों एवं कल्याणकारी कार्यों को विकसित करना।
6. स्थानीय सरकार की प्रोत्साहन देना।
7. सहकारिता एवं सहकारी कार्यों को बढ़ावा देना।

उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समय–समय पर अनेक राज्यों द्वारा अनेक प्रकार की जरूरतमंद विकास योजनाओं का संचालन किया गया।

ग्रामीण जनशक्ति कार्यक्रम 1968–69, ग्रामीण रोजगार कैश कार्यक्रम 1972–72, पाइलट पहल ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम 1972–73, सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम 1973–74, मरूस्थल कार्यक्रम 1977–78, काम के बदले अनाज योजना 1977–78, अन्त्योदय 1977–78।

इनके अलावा कुछ वृहत कार्यक्रम भी चलाये गये – जिनमें :– ग्रामीण आवासी योजना 1957–58, ग्राम विद्युतीकरण योजना 1969–70, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 1974–75, कोष सूत्रीय कार्यक्रम 1975–76, राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम 1982–83, इन्दिरा आवास योजना 1985–86, कुटीर ज्योति कार्यक्रम 1988–89, दस लाख कूप योजना 1989–90, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम 1990–91, सांसद स्थलोप क्षेत्र कार्यक्रम 1993–94, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम 1993–94, गांधी ग्राम योजना 1995–96, ग्रामीण सम्पर्क मार्ग योजना 1997–98, स्वर्ण जयन्ती ग्राम योजना 1997–98, टेक्नोलॉजी मिशन कार्यक्रम 1998–99।

इनके अतिरिक्त क्षेत्र पंचायत के ग्रामीण समुदाय के विकास हेतु कमजोर व पिछड़े वर्गों, बालकों, महिलाओं, वृद्धों और विकलांगों को विशेष सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके सशक्तिकरण के लिए निर्धनता विरोधी कार्यक्रम संचालित किये गये – ग्रामीण समुदाय के विकास हेतु प्रमुख नयी योजनाएं इस प्रकार रहीं:– स्वर्ण जयन्ती ग्राम – स्वरोजगार योजना 1999–2000, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999–2000, अन्नपूर्णा योजना 1999–2000, शिक्षा गारंटी योजना 1999–2000, शिक्षा मित्र योजना 1999–2000, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999–2000, स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण आवास वित्त योजना 1999–2000, बाल विद्या बीमा योजना 1999–2000, जनश्री बीमा योजना 2000–01, ग्रामोदय योजना 2000–01, किशोरी शक्ति योजना 2000–01, सर्वशिक्षा अभियान योजना 2000–01, सर्व प्रिय योजना 2000–01, प्रधानमंत्री ग्रामोदय ग्रामीण आवास योजना 2000–01, क्रेडिट कम सब्सिडी आवास योजन 2000–01, अन्त्योदय अन्न योजना 2000–01, जलविधि योजना 2000–01, ग्राम स्वराज योजना 2000–01, बालुगू निर्धनता उन्मूलन 2000–01, जिला निर्धनता उन्मूलन 2000–01, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000–02, खेतिहर मजदूर बीमा योजना 2001–02, शिक्षा सहयोग बीमा योजना 2001–02, आश्रम बीमा योजना 2001–02, शैक्षणिक ऋण योजना 2001–02, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 2001–02, जयप्रकाश नारायण रोजगार गारंटी योजना 2001–02, स्वजल धारा योजना 2001–02, राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना 2002–03, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 04 अप्रैल 2005, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम 12 अप्रैल, 2005, भारत निर्माण कार्यक्रम 16 दिसम्बर 2005, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम 2 फरवरी 2006।

निष्कर्ष

सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य सम्पूर्ण ग्रामीण भारत का समन्वित विकास करना जिससे ग्रामीणों का सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक दृष्टि से उत्थान हो सके। इस कार्यक्रम में ग्रामीण जीवन स्तर को उन्नत करने के लिए ग्रामीण जनता के सक्रिय सहयोग पर विशेष जोर दिया गया है। इसमें कृषि को जो कि ग्रामीण जनता के करीब 70 प्रतिशत लोगों का मुख्य आश्रय है, सबसे अधिक प्राथमिकता दी गयी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि के अतिरिक्त यातायात, संचार के साधनों का विकास एवं स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास स्त्रियों, बच्चों, वृद्धों का कल्याण, कुटीर लघु–उद्योग तथा रोजगार की व्यवस्था आदि आते हैं।

भारत जैसे देश में नियोजित विकास या परिवर्तन की नितांत आवश्यकता है। यह ऐसा देश है जहां जनसंख्या प्रतिवर्ष बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। किन्तु कृषि उत्पादन काफी निम्न है। यहां मृत्युदर काफी ऊँचा है। परन्तु स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। यहाँ निरक्षरता काफी पायी जाती है और शिक्षा सुविधाओं की कमी है। ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त विभिन्न समस्याओं के विकराल रूप को ध्यान में रखकर ही सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण सामुदायिक विकास योजनाओं को विशेष महत्व दिया है। प्रारम्भ में यह कार्यक्रम इस मान्यता पर आधारित था कि गांव के लोग अपने जीवन के ढंग को सुधारने के लिए काफी उत्सुक एवं तत्पर होंगे। उन्हें केवल कुछ वित्तीय सहायता और प्रौद्योगिकी मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अतः लोगों द्वारा अनुभव की जाने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति पर विशेष ध्यान दिया गया। साथ ही यह भी अनुभव किया गया कि ग्रामीणों में परिवर्तन के लिए एक प्रबल इच्छा जागृत करना और यह भावना कि देश की

विकास योजनाओं के निर्माण तथा कार्यान्वयन में वे सक्रिय भागीदार है, अत्यन्त आवश्यक है। सामुदायिक विकास के अध्ययनों से ज्ञात होता है कि इसके चार मूल तत्व हैं :–

1. नियोजित कार्यक्रम जिसे समुदाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
2. विकास कार्यों में ग्रामीणों की सहभागिता और पहल।
3. विशेषज्ञ, सामग्री और साधन के रूप में सहायता।
4. समुदाय की सहायता के लिए विभिन्न विशेषज्ञों का सामंजस्य जैसे कृषि, पशुपालन, जन स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज सेवा आदि।

अंत टिप्पणी

1. *Community Development programme in India, 1955, Community Project Administration Govt. of India, p-4.*
2. *Day, S.K. Nilokheri, Bombay, 1961*
3. *United Nations – Community Extension Division, Community Development Department, Ministry of Interior, Community Extension.*

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *ए0एन0 सिंह, सामुदायिक संगठन, 2012, हरियाणा ग्रन्थ अकादमी, पंचकुला।*
2. *सुरेन्द्र कटारिया, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, 2004, भोपाल।*
3. *निर्मल सिंह, पंचवर्षीय योजनाओं में उ0प्र0 में कृषि विकास, 2009, दिल्ली।*
4. *एस0एस0 जौहर, भारत में सामुदायिक विकास, 1964, नई दिल्ली।*
5. *ए0ए0 अग्रवाल, भारतीय अर्थ व्यवस्था, 2005, दिल्ली।*
6. *ए0आर0 देसाई, भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि, 1968, बम्बई।*
7. *एच0एस0 वर्मा, पोस्ट इंडिपेन्डेंस चेंज इन रूरल इंडिया, 1991, दिल्ली।*
8. *प्लानिंग कमीशन रिपोर्ट्स – प्रथम पंचवर्षीय योजना (1957) भारत सरकार।*
9. *जे0एस0 श्रीवास्तव, कृषि अर्थशास्त्र, 2007, दिल्ली।*